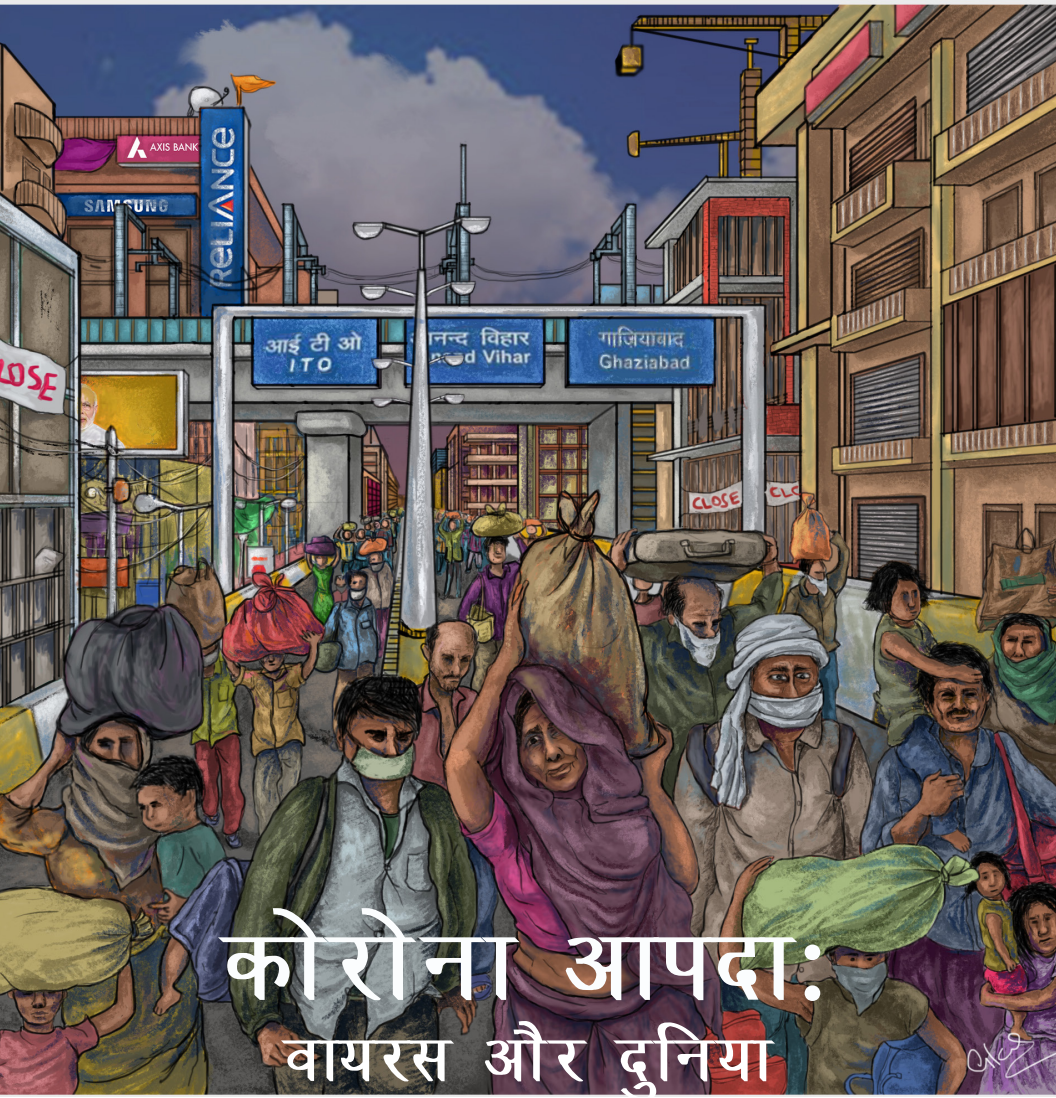

कोरोना आपदा:
वायरस और दुनिया

डोजियर नं. 28
ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान
मई 2020

इस डोजियर 'कोरोना आपदा: वायरस और दुनिया' के लिए हमने दुनिया भर के कलाकारों और कार्यकर्ताओं को कोरोनाशॉक स्केचबुक में क्वारनटाइन के दृश्य प्रतिबिंब शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। नवउदारवाद –विशेष रूप से लचीली और खंडित काम की व्यवस्था जिससे क्वारनटाइन में भी काम करना संभव है– के विमानुषिकरण को जब हम जी रहे हैं, ठीक तभी मानव और आर्थिक जीवन से खाली हो चुकीं हमारी सड़कें और हमारे सार्वजनिक स्थान भी विमानुष हो गए हैं। दिल्ली में प्रवासियों के पलायन से लेकर बार्सिलोना और कुआलालंपुर की अनिश्चित महिला श्रमिकों की दुर्दशा से एक ही सवाल उठता हैरू आवश्यक सेवाएँ कौनसी हैं और उन्हें बनाए रखने वाले कर्मचारी कौन हैं? ब्यूनस आयर्स के खाली करवाए गए प्लाजा डे मेयो से लेकर दक्षिण अफ्रीका में बस्तियों से बेदखल किया जाना, न्यू यॉर्क सिटी के आपातकालीन निकासों से लटके बैनरों से लेकर साओ पाउलो में बर्तन बजा कर किए गए विरोध–प्रदर्शनों (पनेलकोस) की आवाजों में, हम सोचते हैं किरू सामाजिक दूरी बनाए रखने के समय पर जन–प्रतिरोध का आकार/तरीका क्या हो सकता है? क्यूबा की चिकित्सा ब्रिगेड का स्केच और चीन की नागरिक सामूहिकता हमें इस समय पर राज्य के नेतृत्व में मानव एकजुटता की महत्वता की याद दिलाते हैं। ये स्केचबुक मौजूदा परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण देकर सवाल उठाती है कि इन खाली और सुनसान सड़कों व सार्वजनिक स्थानों को हम फिर से कैसे भर सकते है और मानवीय बना सकते हैंय ये हमें कोरोनावायरस के बाद के जीवन की कल्पना करने की प्रेरणा भी देती है।

कवर चित्र: 'घर', भारत के प्रवासी मजदूरों के लिए एक दूर का सपना, दिल्ली, भारत।

विकास ठाकुर / ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान

भारत में सरकार द्वारा तालाबंदी की घोषणा के बाद, अपने घर पहुँचने के लिए प्रवासी मजदूरों ने देश भर में पैदल यात्राएँ की। ये वो मजदूर हैं, जो महामारी से पहले भी, थोड़े से भोजन के लिए रोजाना संघर्ष करते थे – और अब COVID–19 की मार झेल रहे हैं।

कोरोना आपदा :
वायरस और दुनिया

डोजियर नं. 28
ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान
मई 2020

दिसंबर 2019 में वुहान (चीन) में डॉक्टरों को एक प्रकार के विषाणुजनित निमोनिया के लक्षणों वाले मरीज मिलने शुरू हुए। दिसंबर के अंत तक इस बाबत जाँच शुरू कर दी गई। चीन के स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक चेतावनी जारी की और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को इसकी सूचना भेज दी। इन्होंने 7 जनवरी को एक नये तरह के कोरोना विषाणु को अलग किया और 12 जनवरी को इसके अनुवांशिक अनुक्रम को साझा किया ताकि इसका उपयोग करके चिकित्सकीय जाँच उपकरणों को तैयार किया जा सके। सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी जनता ने इसको फैलने से रोकने के लिए वृहद् स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए। यह रहस्यमय रोगाणु एक तरह का कोरोना विषाणु था जिसको आधिकारिक रूप से SARS-CoV-2 नाम दिया गया। यह दूसरे श्वसनतंत्रीय विषाणुओं से इसलिए अलग है क्योंकि यह नाक, गले और फेफड़ों में भी जिंदा रह सकता है। गले में मौजूद रहने से इसके फैलने की संभावना काफी ज़्यादा होती है। फेफड़ों में मौजूद कोरोना विषाणु के लक्षण तुरंत सामने नहीं आते लेकिन मरीज के लिए फेफड़ों में इसकी मौजूदगी जानलेवा होती है। यह पूरी दुनिया में काफी तेजी से फैला है। लगभग हर देश इससे प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से लॉकडाउन और लोगों को अलग निगरानी में रखने की नौबत आ गई है। सामाजिक और आर्थिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। हालाँकि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में इसपर नियंत्रण पा लिया गया है लेकिन इसके दोबारा वापस आने और कोरोना विषाणु से जुड़ी हुई दूसरी हजारों समस्याओं के लिए तैयार रहना होगा। 1832 के हैजा और 1918 के फ्लू की तरह ही यह महामारी भी चक्रबद्ध तरीके से वापस आएगी।

अधिकाधिक लोगों के संक्रमित होने और हजारों लोगों की मृत्यु के कारण एक के बाद एक कई देशों को अलग–अलग समय के लिए लॉकडाउन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है । लोगों को अलग–अलग और क्वारंटाइन में रखे जाने के आदेशों की वजह से आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना आपदा के कारण 2.5 करोड़ नौकरियाँ चली जाएँगी और साल के अंत तक मजदूरों को आमदनी में 3.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान सहना पड़ेगा। व्यवसायों और कॉर्पोरेटों के द्वारा कोरोना आपदा का फायदा उठाकर कम मजदूरों से काम चलाकर अपनी व्यवस्था को 'दक्ष' बनाने की जो कोशिश हो रही है इससे स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संकेत दिए हैं कि लम्बे समय तक बनी रहने वाली बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्या के साथ–साथ तेल बाजार की अनिश्चितता के कारण वैश्विक विकास दर घटकर 1% के करीब रहने वाली है। यह विकास दर भी चीनी विकास दर पर आश्रित है। चीनी विकास दर कोरोना के कारण घटी तो है, लेकिन चूँकि इसको देश की सीमा के भी भीतर ही नियंत्रित कर लिया गया, इसलिए चीनी विकास दर के बढ़ने के आसार हैं। हांग सेंग से लेकर वॉलस्ट्रीट तक स्टॉक बाजारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। उनके बढ़े हुए मूल्य गिर गए हैं।

सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा आपातकालीन वित्तीय मदद की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रया कोष (15 मिलियन डॉलर), विश्व बैंक (12 बिलियन डॉलर), और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (1 ट्रिलियन डॉलर) ने पैसा इकट्ठा किया है। केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय संस्थानों और कंपनियों को पैसे देने के लिए नयी तरह की सुविधाएँ शुरू की हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने एक बिल पारित कर के

आपातकालीन कोष को 2.2 ट्रिलियन डॉलर की राशि दी है। इसका ज़्यादातर हिस्सा कॉर्पोरेशनों को उबारने के उपयोग में लाया जाएगा। इससे यह बात साबित हो गई है कि समस्या वित्तीय बाजारों में नकदी की कमी की नहीं थी, जिसकी वजह से 2008–2009 का वित्तीय संकट आया था। यह संकट घटनाओं की एक शृंखला का नतीजा है : कोरोना वायरस की अनिश्चितता, तेल की कीमतों में भारी कमी और लम्बे समय से बनी हुई बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्या। हालाँकि पैसे को कोरोना आपदा का सामना करने के लिए जुटाया गया है, लेकिन मसला ये है कि इसे वास्तव में खर्च कैसे किया जाएगा। पूँजीवादी समाज में पैसों को बैंकों और विशाल कॉर्पोरेटों को दे देने की आदत होती है। लेकिन पिछले अनुभव हमें बताते हैं कि ये पैसों को का उपयोग समस्या के निराकरण के लिए चिह्नित लक्ष्यों के लिए शायद ही करते हैं। सामाजिक गैरबराबरी के दीर्घकालिक समाधान के लिए और जनता के लिए आमदनी और रोजगार पैदा करके उनको राहत देने के लिए इन पैसों का उपयोग कम ही किया जाता है। इसीलिए ट्राइकॉन्टिनेंटल: इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च और इंटरनेशनल असेंबली ऑफ द पीपल्स ने एक दस्तावेज का निर्माण किया है, जिसके 16–सूत्री कार्यक्रम को डोसियर के भाग 2 में दिया गया हैं, जो कोरोना आपदा से जूझने के लिए दुनिया के लोगों के दृष्टिकोण के आधार पर तैयार किया गया है। कोरोना आपदा: वायरस और दुनिया तीन हिस्सों में विभाजित है। भाग 1 उन संरचनात्मक विशेषताओं पर है जिसके परिण ामस्वरूप हमारा वर्तमान संकट पैदा हुआ है। भाग 2 इंटरनेश्नल एसेम्बली ऑफ पीपुल्स एडंट्राईकॉन्टिनेंटल: इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च के 16–सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में है। इस कार्यक्रम में एक बिंदु यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी है। यह एक जटिल विचार है जिस

पर चर्चा की आवश्यकता है। हमारे डोसियर के भाग 3 में हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के विचार के विषय में एक संक्षिप्त परिचय दिया है साथ ही इस अवधारणा की आलोचना तथा इस विषय में समझ विकसित करने के तरीकों के बार में भी चर्चा की गई है।

NUNCA MÁS (अब नहीं)

हवाना, क्यूबा

कलिया वेनेरेओ / डोमिनियो क्यूबा

'नवउदारवादी नीतियां जो लोगों को स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित करती हैं #अब–नहीं (#NeverAgain)'। यह तस्वीर क्यूबा के डॉक्टरों को दर्शाती है जिन्होंने एकजुट रह कर महामारी पर जीत हासिल करने का फैसला किया है। यह तस्वीर डोमिनियो क्यूबा नामक एक संगठन ने, फ्रेंच संगठनों और मशहूर हस्तियों के द्वारा, नवदारवादी नीतियों –जो लोगों को स्वास्थ्य के अधिकार से भी वंचित रखती हैं– के बिना एक भविष्य बनाने के लिए दुनिया भर में सोशल मीडिया अभियान चलाने हेतु एक दीक्षांत समारोह के समर्थन में बनाई थी।

भाग 1. उदारवादी वायरस

वैश्विक महामारी हमें अपने नवउदारवादी चरण में पूँजीवाद की स्पष्ट विनाशकारी प्रवृत्तियों को दिखाती है। आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती और शेयर बाजारों में उथल–पुथल के इस संयोजन ने नवउदारवादी पूँजीवादी नेताओं और बहुपक्षीय संस्थानों को कीनेसियन (ऐसा आर्थिक सिद्धांत जो मानता है कि आर्थिक विकास का मुख्य आधार उपभोक्ता की माँग है) में बदल दिया है – चाहे वो एंजेला मार्केल (जर्मनी) और इमैनुअल मैक्रॉन (फ्रांस) हों या विश्व बैंक और आईएमएफ। इनमें से प्रत्येक ने निजी क्षेत्र में पैसा डालने के लिए (और राज्य कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए) अपने केंद्रीय बैंकों और अपने वित्त मंत्रालयों के दरवाजे खोले हैं। दूसरी ओर, इसने कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेताओं को आगे बढ़ाया है– जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प (यूएसए), नरेंद्र मोदी (भारत), जेयर बोल्सोनारो (ब्राजील), रेसेप तैयप एर्दोआन (तुर्की), और विक्टर ओरान (हंगरी)। जिन्होंने नस्लीय घृणा सहित अपने घृणित कार्यक्रमों को और सख्त किया हैं, जिनपर ये पहले से अमल कर रहे हैं। क्योंकि महामारी की चेतावनी मिलने के काफी समय बाद भी, महामारी से निपटने में विफल रहने तथा इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाये इन्हें इस वायरस के लिए चीन को दोषी ठहराना कहीं अधिक आसान था। उत्तरी अटलांटिक देशों के इन नेताओं और जिन संस्थानों को वे नियंत्रित करते हैं, उन्होंने इस संकट की स्थितियों को बनाया, जिससे दुनिया के लोगों के लिए एक अस्थिर सामाजिक स्थिति पैदा हुई है– खासकर दक्षिणी गोलार्ध के देशों के लिए। उन्होंने इस संकट को इस तरह प्रस्तुत किया कि यह केवल उन परिस्थितियों के एक साथ इकट्ठा होने से उभरा है जिनकी महामारी द्वारा पूरी तरह से व्याख्या की जा सकती है; सुर्खियों में घोषणा की गई कि 'संकट को कोरोनोवायरस द्वारा उकसाया गया

है।' अन्य वायरस की तरह ही यह वायरस भी जंगलों में मानव अतिक्रमण और मानव सभ्यता (कृषि और शहरों) तथा जंगल के बीच संतुलन के मूलभूत प्रश्न को उठाता है। जैसा कि मिगुएल टिंकर सालास और विक्टर सिल्वरमैन ला जोर्नडा में लिखते हैं, वायरस प्रकृति का उत्पाद है, जबकि संकट नवउदारवाद का उत्पाद है।

हालाँकि, 1970 के दशक से (और 1991 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद से सबसे अधिक तीव्रता से) नवउदारवादी वैश्वीकरण परियोजना ने अमानवीयता को असाधारण रूप से बढ़ावा दिया है – जिनमें सार्वजनिक संस्थानों में कटौती और सामाजिक नीतियों में उदारीकरण की प्रक्रिया शामिल है। अक्सर अनिश्चित काम और उससे उपजी अशांति, मांग को बढ़ावा देने के लिए बहुत कम आय वाले लोगों को दिया जाने वाला ऋण, जिसे वे चुका नहीं सकते और उद्योग से वित्त क्षेत्र की ओर पूँजी का अत्यधिक स्थानांतरण अमानवीय संकटों के चक्र को और तेज कर देता है। जो संकट उभरकर सामने आया वो पूँजीवाद को चुनौती देने वाले लोकप्रिय संघर्षों के उभार से नहीं आया, बल्कि वह अपने नवउदारवादी दौर में पूँजी के अमानवीय तर्क से आया है। उन उपायों के माध्यम से संकटों का समाधान किया गया जो अक्सर बीमारी से भी बदतर थे।

नोवेल कोरोनोवायरस की उत्पत्ति और इससे होने वाले संकट ने पूँजीवादी सभ्यता के ह्रास को उजागर कर दिया है। महामारी के नियंत्रित होने के बाद शायद दुनिया वैसी नहीं होगी। नष्ट होते नवउदारवादी राज्य की जगह या तो एक ऐसी राज्य संरचना लेगा जो नवफासीवादी परियोजना का पक्षधर हो, या फिर एक ऐसी राज्य संरचना जो सार्वजनिक संस्थान निर्मित करे तथा अपनी नीतियों में लाभ की जगह जनता की आवश्यकता को

प्राथमिकता दे। यह एक मुश्किल विकल्प है। नवउदारवादी खेमे के कुछ हिस्से में इस बात की बेचौनी है कि कोरोना आपदा के दौरान आपातकालीन आधार पर सामाजिक प्रकृति की जो भी नीतियाँ लागू की जाएँगी उन्हें वापस लेने में मुश्किल आएगी। वर्तमान संकट समाप्त होने के बाद इस अवधि में किए गए बदलाव को वापस लेने तथा पहले की स्थिति में जाने के लिए यथास्थिति को तोड़ने से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी होगी।

वैश्विक महामारी से उत्पन्न संकट स्वास्थ्य के मुद्दे से कहीं अधिक है। वर्तमान की अराजकता और अनिश्चितता से परे, सवाल यह है कि निकट भविष्य में एक नया सामाजिक मॉडल और राजनीतिक व्यवस्था संभव है या नहीं। दार्शनिक स्लावोजीजक और ब्यूंग–चुल हान ने एक चर्चा के बीच भविष्य के बारे में विचार पेश किया: जो कुछ उभरकर आएगा वो किसी तरह के 'पुनः–स्थापित साम्यवादश से मिलता–जुलता होगा, या यह एक तरह के पुलिस राज्य के रूप में विकसित होगा, जो विशाल आँकड़ों (डाटा) से संचालित होगा?

इन सवालों का कोई जवाब पहले से तय नहीं किया जा सकता। वर्तमान संकट पहले से इकट्ठा हो रही प्रवृत्तियों की एक शृंखला का हिस्सा है, जो पिछले दशकों में तेज हुआ और वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप अब जिसमें विस्फोट हुआ है। इस संकट की चार संरचनात्मक अभिलक्षणों पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है: गहराता हुआ वित्तीयकरण, यूएस आधिपत्य में गिरावट, प्रौद्योगिकी द्वारा श्रम का विस्थापन और उत्पादकता में वृद्धि, तथा नवउदारवादी राज्य का संकट।

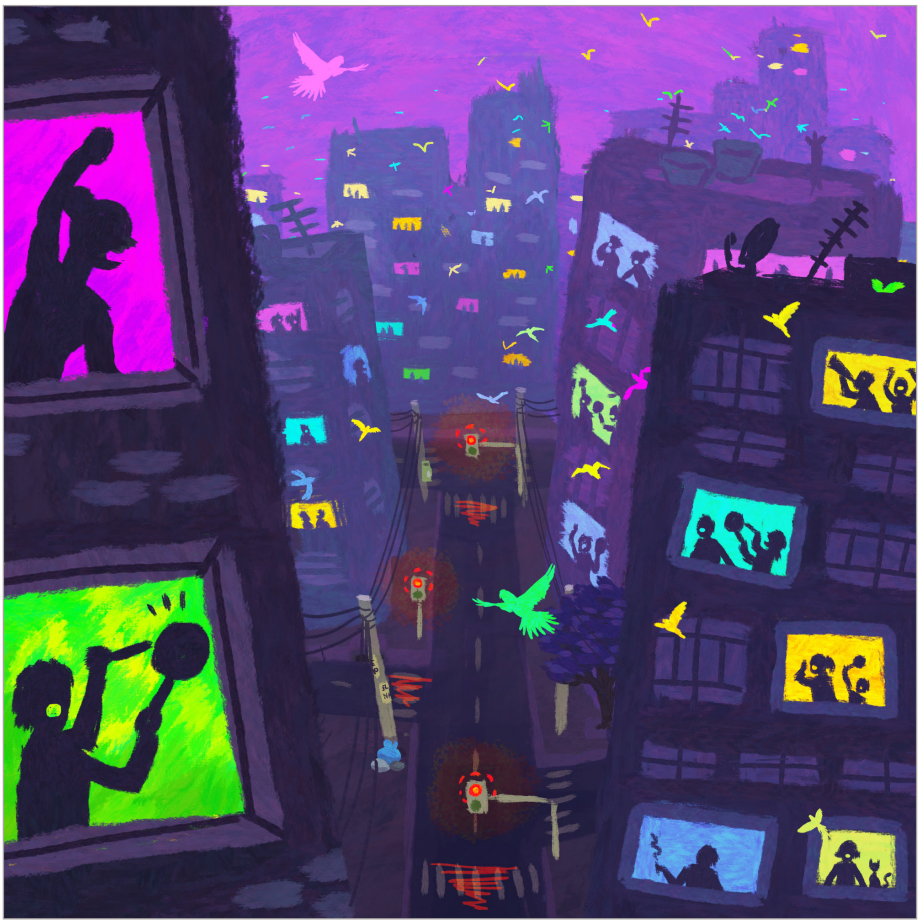

FORA बोल्सनारो!.. बाहर जाओ, बोल्सनारो!

साओ पाउलो, ब्राजील

इंग्रिड नीव्ज / ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान

क्वारनटाइन के दौरान ब्राजील में चल रहे पनेलकोसों (बर्तन बजा कर किए जाने वाले विरोध–प्रदर्शन) में 'बाहर जाओ, बोल्सनारो', 'बाहर जाओ, फासिवादी', और 'वो नहीं' जैसे नारे हवा में गूँजते हैं। सामाजिक दूरी और आइसोलेशन की जरूरत, बड़े शहरों में राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो की सरकार के खिलाफ आवाजों, बर्तनों और विरोध करने वालों को एकजुट होने से रोक नहीं पाई है।

वित्तीयकरण की लहर

2008 के ऋण संकट से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता सुझाया गया वो सही रास्ता नहीं था। यूरोजोन के देशों के साथ–साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा निवेश बैंकों और बड़ी गैर–वित्तीय कंपनियों के लिए अपनाई गई बेलआउट नीति ने वैश्विक हाइपर–लिक्विडिटी (यानी डॉलर की अधिकता) की एक प्रक्रिया उत्पन्न की। जब भी पूँजी कमजोर लाभप्रदता का सामना करती है, तो यह हमेशा सट्टा बाजार और काल्पनिक गतिविधि को प्राथमिकता देती है – उदाहरण के लिए, शेयर बाजारों में भीड़। वर्तमान अवधि में वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में वित्तीय क्षेत्र के परिमाण की सीमा आश्चर्यजनक है और यही वह चीज है जो इसे अद्वितीय बनाता है।

ऐसे कई तत्व हैं जो वित्तीयकरण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह प्रक्रिया 1980 के दशक से गुब्बारे की तरह फूलते हुए वित्तीय क्षेत्र की ओर इशारा करता है, जिसके साथ बड़े पैमाने पर उत्पादक क्षेत्र द्वारा जमा किए गए अधिशेष मूल्य को वित्तीय फर्मों में अवशोषित कर लिया गया। विभिन्न प्रकार के अपरिमित ऋण घरों में इकट्ठा हो गए– विशेष रूप से कामकाजी वर्ग के घरों में रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए; यह ऋण प्रतिभूतियों में पैक किया जाता है और वित्तीय दुनिया के विशाल कैसीनो में चारों ओर उछलता है। हम आर्थिक गतिविधियों में एक गुणात्मक बदलाव देख रहे हैं, जिससे उत्पादन की गतिविधियों से लाभप्रदता के पुराने संकटों के साथ–साथ पूँजी के प्रसार से वित्त की अस्थिरता उत्पन्न होती है।

पैसे की इस अत्यधिक प्रचुरता ने उत्पादक निवेशों की वैश्विक प्रक्रिया को गति नहीं दी। इसके विपरीत, दुनिया का अधिकांश पैसा एक बार फिर से संप्रभु ऋण और वित्तीय परिसंपत्तियों (फिर से सक्रिय स्टॉक खरीद के माध्यम से) में जुड़कर समाप्त हो गया, जिससे वित्तीयकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। सरकारी परिसंपत्तियों के रूप में इस तरह के साधनों के माध्यम से नयी परिसंपत्ति के बुलबुले फुलाए गए, और वित्त ने नयी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कंपनियों को लुभाने के लिए अपनी बाहें खोली।

प्रौद्योगिकी कंपनियों ने शेयर बाजारों पर हावी होना शुरू कर दिया है, और उन्होंने दुनिया की तरलता का काफी हिस्सा अवशोषित कर लिया हैय यह अवशोषण आम तौर पर पूँजी के केंद्रीकरण की विशेषता थी, विशेष रूप से अमेरिकी फर्मों में (ऐप्पल, अमेजॅन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, और फेसबुक ऐसी कंपनियाँ थीं जिनका मूल्यांकन सबसे अधिक था)। इन अमेरिकी प्रौद्योगिकी फर्मों को मूल रूप से हुआवेई जैसे चीनी प्रौद्योगिकी फर्मों के विकास से चुनौती मिली है। 5जी जैसे क्षेत्रों में हुआवेई के आगे बढ़ने से बौद्धिक संपदा अधिकारों के दावों पर अमेरिकी कंपनियों के वर्चस्व को चुनैती मिल रही है, इन बौद्धिक संपदाओं के एकाधिकार से इन्हें किराए के रूप में काफी धन मिल जाता था। चीन के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए व्यापार युद्ध से इस बात को सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि चीनी प्रौद्योगिकी फर्मों ने शक्तिशाली अमेरिकी प्रौद्योगिकी फर्मों के सामने खतरा उत्पन्न कर दिया है।

उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के देशों में वित्तीयकरण में वृद्धि दर्ज कीया गई है। उत्तरी गोलार्ध में वित्त ने पूँजी को नये अति–लाभकारी क्षेत्रों (जैसे प्लेटफॉर्म पूँजीवाद, (ऊबर

फेसबुक आदि इसका उदाहरण है) और प्रौद्योगिकी) में पहुँचा दिया है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वित्त में पूँजी के प्रवाह के कारण ऋणग्रस्तता की गति में तेजी आई है। 2015 में यूएस फेडरल रिजर्व ने फेडरल फंड्स रेट (दो रात के बीच का दर जो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस लोन के लिए एक–दूसरे को चार्ज करते हैं) को बढ़ाकर अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने की नीति अपनाई, इसके बाद दुनिया के बाकी हिस्सों से वहाँ पैसा आया जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। इस तरह की नीतियों के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका एक दशक बाद फिर से वैश्विक पूँजी के लिए मुख्य गणतव्य स्थान बना, क्योंकि इस बीच वैश्विक पूँजी 'उभरते हुए बाजारों' की ओर जा रही थी। 2018 में, सबसे अधिक शुद्ध पूँजी प्रवाह वाले तीन देश संयुक्त राज्य अमेरिका (258 बिलियन डॉलर), चीन (203 बिलियन डॉलर) और जर्मनी (105 बिलियन डॉलर) थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया की तरलता का एक बड़ा हिस्सा आकर्षित किया, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व की उच्च ब्याज दरों की नीति है; इसने पूँजी को दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आकर्षित किया।

समाज और अर्थव्यवस्था पर वित्त के गहरे प्रभाव ने तीन परिणामों को जन्म दिया है: आर्थिक रूप से ऋणग्रस्त दक्षिणी देशों की राजनीतिक निर्भरता, उत्तरी गोलार्ध में अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ठहराव, और विश्व प्रणाली की दीर्घकालिक अस्थिरता, जो पूँजी के हित को लोगों की जरूरतों से अधिक महत्व देता है। कोरोनावायरस की उपस्थिति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। चीन वैश्विक विनिर्माण के लिए केंद्रीय बन गया है। चीन में उत्पादन का ठहराव, और इसके औद्योगिक उत्पादन में 15% की गिरावट (पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में), के बीच यह समझना मुश्किल है कि

उत्तरी गोलार्ध में बड़े बैंकों की तरलता न केवल वैश्विक आपूर्ति शृंखला को बल्कि कुल वैश्विक मांग को कैसे पुनर्जीवित करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की गिरावट में तेजी

गियोवन्नी अरिघी ने अपनी किताब एडम स्मिथ इन बीजिंगरू लीनिएजेज ऑफ ट्वेंटी–फर्स्ट सेंचुरी (2007) में विचार किया है कि वित्तीयकरण की प्रक्रिया में बढ़ौतरी और तेजी को अमेरिकी आधिपत्य के संकट का सूचक माना जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरेशिया में चीन पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए कई गुटनिरपेक्ष राज्यों (ईरान और वेनेजुएला) के खिलाफ मिश्रित युद्ध चलाया है, और इस प्रक्रिया में उसने अपनी वित्तीय शक्ति का उपयोग किया है, साथ–ही–साथ अपने सहयोगियों पर फिर से अपनी श्रेष्ठता स्थापित की है। इस वैश्विक महामारी के कारण बढ़ रहे स्वास्थ्य और मानवीय संकट ने चीन की भूमिका को मजबूत किया है। विशेष रूप से, अपनी सीमाओं के भीतर वायरस को नियंत्रित करने में सक्षम राज्य के रूप में, और फिर अपने देश से बाहर पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करने के लिए। दूसरी ओर, ट्रम्प का अपने ही लोगों के प्रति घिनौना रवैया – मानवीय आपदा से पहले अर्थव्यवस्था की 'चिंता' करना – अमेरिकी नेतृत्व के पतन को स्पष्ट करता है, क्योंकि अमेरिका किसी भी तरह की राहत कार्रवाई का नेतृत्व करने में विफल रहा – जी–20 तक के प्लेटफॉर्म से भी नहीं, जिस पर आम तौर पर उसका वर्चस्व रहा है। भविष्य में क्या होगा इस बारे में अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता– कि हम एशियाई सदी में प्रवेश करेंगे या द्विध्रुवीय युग में या बहुध्रुवीय युग में – लेकिन यह स्पष्ट है कि

पश्चिमी उदारवादी सभ्यता अपने ही हिस्से की दुनिया में अपने ही लोगों की जरूरतों को पूरा करने में भी सक्षम नहीं थी।

श्रम के खलिाफ डिजिटलीकरण

प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पूँजी के संचयन की ओर हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए। यह कम–से–कम दो महत्वपूर्ण बहसें खड़ी करता है: पहला, कि यह उच्च तकनीकी कंपनियों पर केंद्रित सट्टा परिसंपत्ति रूपी बुलबुला उत्पन्न करता है, और दूसरा, यह दुनिया भर में वैश्विक पूँजीवाद के प्रभाव का विस्तार करता है और साथ ही डेटा के नियंत्रण की अनुमति भी देता है, जिससे लोगों को नियंत्रित किया जा सके। 'प्लेटफॉर्म पूँजीवाद' की तेज वृद्धि – या आर्थिक गतिविधि जो इंटरनेट–आधारित प्लेटफॉर्म में निहित है – और बड़े डेटा के संग्रह और विश्लेषण से उपभोक्तावाद के नये तर्कों का निर्माण करता है; जिसे चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जाता है उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्लेटफॉर्म पूँजीवाद उपभोक्ता जरूरतों को गढ़ता है और उस तक पहुँचाता है, आत्म–चेतना के नये रूपों का निर्माण करता है, और यहाँ तक कि राजनीतिक पहचान बनाने में भी हस्तक्षेप करता है। सामाजिक गतिविधि के एकाकीपन के माध्यम से वैयक्तिकरण के समग्र निर्माण ने इस दुनिया में जीने के नये तरीके खोजे हैं।

वैश्विक महामारी और दुनिया के बड़े हिस्से में होने वाले लॉकडाउन प्लेटफॉर्म पूँजीवाद के विकास के लिए अनुकूल है। इंटरनेट के उपयोग से कोवारंटाईन के दौरान दूर बैठकर काम जारी रखा जा सकता है। गूगल, अमेजन, फेसबुक और जूम ने घर से काम करना संभव बना दिया है, और उन्होंने सुझाव दिया है कि यह दुनिया के श्रमिकों के

कौन चलाता है जीवन?

न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स

बेलन मार्को क्रेस्पो / द पीपल्स फोरम

मजदूर वर्ग कोविद–19 के प्रकोप से बहुत पहले से ही पूँजीवाद के व्यवस्थागत संकट का सामना कर रहा है और यह अभी भी मजदूर वर्ग ही है, जिसने ख़सबका, जीवन चालू रखा है। न्यूयॉर्क में आप्रवासी, अनौपचारिक और कम वेतन वाले श्रमिकों, और महिलाओं ने ही ऐसे समय में देखभाल–कार्य का बोझ उठाया है जब पूरी मानव–जाति को मुनाफे से पहले देखभाल को प्राथमिकता देने की जरूरत है।

लिए फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, वे सुझाव देते हैं कि हम अपने समय का अधिक स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम होंगे, और हम–लचीले अनुबंधों के माध्यम से– अधिक आवृत्ति के साथ नौकरियाँ बदल सकते हैं। बेशक, पूँजीवाद के तहत श्रमिकों के लिए जीवन भर के रोजगार का विचार अब असंभव है, और लचीला काम नवउदारवाद के इस दौर का प्रतिमान बन गया है। ऐसी नौकरियों के लिए जो दूर बैठकर करना संभव है, यह मॉडल असंगत श्रम के बढ़ते बोझ को भी नजरअंदाज करता है। काम के दौरान उन्हें दूसरे घरेलू काम भी करने होते हैं – जैसे कि उन बच्चों की देखभाल करना जो संकट के कारण स्कूल से बाहर हैं और परिवार के उन सदस्यों की देखभाल करना जिनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। इसके अलावा, इस लॉकडाउन अवधि के बीच में प्लेटफॉर्म पूँजीवाद द्वारा निभाई गई केंद्रीय भूमिका नवउदारवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाता है – विशेष रूप से कार्य बल का विभाजन और श्रमिकों का विखंडन – तथा कार्यबल को पूँजी के स्वतंत्र हितों के अधीन करता है।

नवउदारवादी राज्य का संकट

नवउदारवादी राज्य व्यवस्था ने दिखाया है कि वह अपने मॉडल द्वारा उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है। उदाहरण के लिए, 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नवउदारवादी राज्य व्यवस्था ने भारी मात्रा में पूँजी को वित्तीय प्रणाली और विशेष रूप से बड़े निगमों (जैसे जनरल मोटर्स) में पंप करने में जल्दबाजी की। इस हस्तक्षेप को शवित्तीय कीनेसियनवादश के रूप में, या नवउदारवादी परियोजना को बढ़ावा देने और लाभ उठाने के लिए वित्तीय फर्मों द्वारा डिजाइन किए गए संरचना को बनाए

रखने के लिए राज्य द्वारा दिए गए मदद के रूप में जाना जाता है। बुनियादी मुद्दों को संबोधित नहीं किया गयाय जैसे, अरबों लोगों के लिए आय की कमी जो महँगे और असहनीय ऋण पर गुजर करते हैं।

कई देशों में, विश्वास खो चुके नवउदारवादी और 'तीसरे रास्ते' (या मध्यमार्गी) वाले राजनेताओं ने धुर–दक्षिणपंथी और नवफासीवादी राजनेताओं के आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया। बोलिविया के पूर्व उपराष्ट्रपति अल्वारो गार्सिया लिनेरा इसे पूँजीवादी जोंबी नवउदारवाद का चरण बताते हैं – एक ऐसी उदारवादी परियोजना जो नफरत और विद्वेष का पक्षधर है। इस जोंबी नवउदारवाद के संदर्भ में बुर्जुआ राज्य संकट में प्रवेश करता है, क्योंकि यह जनता की लोकतांत्रिक मांगों को स्वीकार ही नहीं करता–उन्हें पूरा करना तो दूर की बात है। कमजोर हो चुके उदार लोकतांत्रिक संस्थानों पर नवफासीवादी अधिनाय. कवाद का ग्रहण लगा हुआ है ऐसे में 'आपात स्थिति' प्रबल है। राजनीतिक सिद्धांतकार विलियम डेविस ने इस नवउदारवाद की व्याख्या करने के लिए दंडात्मक नवउदारवाद का उपयोग किया है जो उदारवादी नीति, राजकोषीय कठोरता, तथा ऋण का भार लादकर संकट का जवाब देता है, खासकर दक्षिणी गोलार्ध के देशों में। डेविस के शब्दों में, 'यह एक अवसाद की स्थिति पैदा करता है जिसमें सरकार और समाज अपने ही लोगों से घृणा करता है और हिंसा भी।'

भाग 2. वैश्विक महामारी के दौर में, लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें

जो शक्तिशाली लोग सत्ता में बैठे हैं वे संकट के समय में पहले खुद को बचाने का उपाय करते हैं। जब भी कोई वित्तीय संकट आता है, उदाहरण के लिए मंदी को ही लें, जब मंदी आती है तो इसका वास्तविक कारण पता नहीं किया जाता, बल्कि जल्दबाजी में उन्हें ही मंदी से उबरने के लिए व्यापक वित्तीय सहायता दी जाती है जो दरअसल इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं। वैश्विक महामारी सामने उभरकर आई है, ऐसे में सरकारों ने खुद को बचाने के लिए पूँजी के हितों की रक्षा के लिए काफी बड़ी धनराशि अलग रख दी है। केंद्रीय बैंकों ने–अमेरिकी फेडरल रिजर्व के इशारे के बाद– शेयर बाजारों में तरलता लाने के लिए ब्याज दरों में कटौती की है, ताकि धनवान लोग आम जनता की सेहत का ध्यान रखने के बजाये अपने निवेश की सेहत का ध्यान रख सकें।

ऐसे समय में जनता का जो संसाधन सार्वजनिक भलाई के लिए शायद ही इस्तेमाल हो पाता हो वह बहुत तेजी से निजी क्षेत्र को बचाने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समाजवादी नीति वाले राज्य (चीन की तरह राष्ट्रीय सरकारों से लेकर केरल की तरह राज्य सरकारों तक) इस महामारी के रोकने के लिए–आर्थिक नुकसान की परवाह किए बिना–जो भी संसाधन जुटा सकते थे जुटाए हैं। डब्ल्यू.एच.ओ. ने चीन के प्रयासों को शायद 'इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी, चुस्त और आक्रामक रोग नियंत्रण प्रयास' कहा है। इस बीच, बुर्जुआ व्यवस्था अपने महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग करने में विफल रहा है और इन संसाधनों के लिए तर्कसंगत योजना तैयार करने में भी। इटली से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक के लिए मृत्यु दर विनाशकारी रहा है। यह मानवता के खिलाफ एक राजनीतिक अपराध है।

पिछले तीस वर्षों के दौरान यूएसएसआर के पतन और वैश्विक वामपंथियों की कमजोर स्थिति के बाद, वामपंथी ताकतें पिछले पैरों पर धकेल दी हई हैं। अरबपति वर्ग के हितों को रक्षा करने के लिए उत्सुक सरकारों ने करों में कटौती की है और उदारवादी नियन लागू किए हैं, कीमती सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण किया है, और उद्योग तथा वाणिज्य पर से नियंत्रण हटा लिया है। दक्षता के नाम पर बुर्जुआ राज्य ने वर्ग संघर्ष को तेज कर दिया है, श्रमिक संघों और वाम संगठनों पर हमला किया है तथा वाम के कुल जमा ताकत को खंडित करने का प्रयास किया है। गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की वृद्धि, जिसे अक्सर धनाढ्यों के प्रतिष्ठानों द्वारा सहायता मिलती है, उसने राजनीतिक वाम के असर को कम कर दिया क्योंकि इसने लोगों का ध्यान समस्याओं की समग्रता से हटकार एकल–मुद्दे वाले अभियानों की ओर लगा दिया है। किसी को पानी की डिलीवरी में दिलचस्पी थी, किसी को शिक्षा में, लेकिन कोई भी पूरी व्यवस्था पर हो रहे हमले के खिलाफ लोगों को एकत्रित नहीं कर रहा था, जो हमला पूँजीवाद की ओर से हो रहा था।

सभी मोर्चे पर वर्ग संघर्ष के दौर में वामपंथियों के कमजोर पड़ने और मीडिया के हमले के आगे बढ़ने के साथ, जो सामान को सपने की तरह बेचता है, वामपंथ को अल्पकालिक संघर्षों पर काफी ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पूँजीवादी उत्पादन प्रक्रियाओं और राज्य की हिंसा की बढ़ती क्रूरता के खिलाफ संघर्ष के निर्माण के साथ उदारवादी शासन के खिलाफ राहत मिली। कटौती और हिंसा के खिलाफ लोकप्रिय भावना के साथ वामपंथी ताकतों की भूमिका के बिना, श्रम प्रक्रिया की क्रूरता, श्रमिकों की दुर्बलता, बेदखल किए जा चुके श्रमिक वर्ग पर नवउदारवाद और वैश्वीकरण का प्रभाव कहीं अधिक बुरा होता। अल्पावधि की वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद

कमजोर हो चुके वामपंथ ने कई संकटों के लिए समाजवादी दृष्टिकोण वाले कार्यक्रमों का निर्माण किया है; इन कार्यक्रमों में कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिन्हें अध्ययन करने की आवश्यकता है। जहाँ वामपंथी सरकार में रहे हैं उन्होंने पूँजीवाद के स्थानिक संकट से निपटने के लिए नये दृष्टिकोणों के साथ प्रयोग किया है और सामाजिक भलाई के काम के लिए संसाधनों को जुटाने और समाज को बदलने तथा वर्ग संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सहभागिता को विकसित किया है।

वैश्विक महामारी के चीन की सीमाओं से आगे बढ़ने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि जिन समाजों ने अपने सार्वजनिक संस्थानों के महत्व को कम कर दिया है, वे इस वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। अपनी आबादी का परीक्षण करने, यह स्थापित करने के लिए कि कौन संक्रमित रोगी हैं और उनके संपर्क में कौन आए, रोगियों के इलाज और निगरानी के लिए, शट–डाउन शहरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन अवरोधों से समाज को अनावश्यक रूप से नुकसान न हो, चीन सरकार ने अपने संसाधनों के बड़े हिस्से का उपयोग किया। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर भारत और ब्राजील तक जर्जर सार्वजनिक संस्थानों – विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों–ने समाज को कमजोर और असहाय कर दिया है। मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण ने स्नातकों को अपने ऋणों का भुगतान करने के तरीके के रूप में चिकित्सा से अत्यधिक पैसे कमाने के लिए प्रेरित किया है, जबकि अस्पतालों के निजीकरण ने अधिशेष या अस्पताल की अधिकतम क्षमता में कटौती की है। इन अस्पतालों में प्रत्येक बिस्तर और मशीन को अचल संपत्ति माना जाता है जिससे अधिकतम किराये की वसूली होती है। 'जस्ट–इन–टाईम' मेडिसिन निजी लाभ कमाने का फॉर्मूला बन गया है।

उदारवादी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की विफलता अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यह विफलता दो स्तरों पर है, एक तो ऐसे संस्थान नहीं बनाए गए जो आपातकालीन स्थिति में असहाय लोगों की देखभाल कर सके, दूसरा, जनभागीदारी वाली ऐसी संस्कृति को विकसित करने में वैश्विक विफलता रही है जो संकट के समय श्रमिक संगठनों तथा सामाजिक समूहों को समुदायों की मदद करने के लिए प्रेरित कर सके। जिन देशों में नवउदारवाद और उदारवाद ने सार्वजनिक संसाधनों को नरभक्षणी की तरह निगल लिया है वहाँ राज्य और समाज की इस विफलता को वायरस के प्रकोप के कारण उचित नहीं ठहराया जा सकता हैय ऐसा क्यों था कि अधिक मजबूत राज्यों और सार्वजनिक सहभागिता की परंपरा वाले देश अधिक प्रभावी रूप से वायरस को रोक सके?

बहुत अमीर लोगों की प्रमुख उपलब्धियों में से एक राज्य संस्थानों के विचार की वैधता पर सवाल खड़ा करना रहा है। पश्चिम में, यह आदर्श रवैया रहा है कि सरकार को प्रगति विरोधी बताकर उसपर हमला किया जाए। सेना को छोड़कर सभी सरकारी संस्थानों को समेट देना लक्ष्य रहा है। एक मजबूत सरकार और राज्य संरचना वाले किसी भी देश को श्सत्तावादीश के रूप में चित्रित किया गया। लेकिन इस संकट ने उस दृश्य को हिला दिया है। चीन जैसे मजबूत राज्य संस्थानों वाले देश जो इस महामारी को संभालने में सक्षम हैं, उनको आसानी से सत्तावादी बताकर खारिज नहीं किया जा सकता है। बल्कि एक सामान्य समझ उभरकर आई है कि ये सरकारें और उनके राज्य संस्थान अधिक सक्षम हैं। इस मामले में और अधिक बहस नहीं की जा सकती कि जड़ और खोखली बुर्जुआ राज्य व्यवस्था राज्य संस्थानों की उस प्रणाली की तुलना में अधिक सक्षम है जो अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हुए सक्षम बने हैं।

पूरब लाल है।

शंघाई, चीन

टिंग्स चाक / ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान

4 अप्रैल को सुबह 10 बजे, चीन में ब्ट्प्क–19 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में मरने वालों की याद में तीन मिनट का मौन रखा गया– उस दिन पूर्वजों की याद में मनाया जाने वाला त्योहार, किंगिंग, था। पूरा देश रुका हुआ था और हवा सायरन, कारों और जहाज के भोंपू और घंटाघर में बज रहे गीत 'पूरब लाल है' की आवाजों से भरी गई थी।

हमने न केवल चीन से, बल्कि क्यूबा, वेनेजुएला और भारतीय राज्य केरल से भी कुछ सीखा है, वह यह है कि अगर कोई समाज जन संगठनों (ट्रेड यूनियनों, महिला संगठनों, छात्र संघों, युवा संगठनों, सहकारी समितियों) द्वारा संगठित किया गया हो, तो उनके पास सार्वजनिक कार्रवाई की क्षमता होती है। एक संगठित समाज वह है जो सामान्य समय में सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए लोगों की क्षमता का निर्माण करता है– संकट में और भी अधिक। समाजवादी परियोजना केवल आंशिक रूप से राज्य के संस्थानों के माध्यम से विकसित की जाती हैय दूसरा हिस्सा – सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा–है समाज के लिए संगठित और सक्रिय होना और सामाजिक निर्माण के रोजमर्रा और असाधारण काम के लिए तैयार रहना।

वैश्विक महामारी का दायरा बढ़ने के साथ ही ट्राइकॉन्टिनेंटल: इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च और इंटरनेशनल पीपुल्स असेंबली (IPA), लगभग सौ देशों के दो सौ से अधिक संगठनों के एक मंच ने इस संकट तथा वैश्विक श्रमिक वर्ग की तात्कालिक जरूरतों पर चर्चा शुरू की। हमने जो दस्तावेज तैयार किया है उसमें 16–सूत्री कार्यक्रम भी है जो आंदेलनों, यूनियनों और राजनीतिक दलों से उभरने वाले संघर्ष तथा शासन व्यवस्था के अनुभवों के आधार पर तैयार किया गया है। प्रत्येक नीति और बिंदु पर बहस करने से अधिक यह कार्यक्रम इस बात पर बहस करता है कि राज्य और उसके संस्थानों की प्रकृति को किस तरह समझा जाए।

1. आवश्यक चिकित्सा और रसद कर्मियों तथा खाने और जरूरी चीजें बनाने और पहुँचाने के काम को छोड़कर सभी काम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, इस प्रक्रिया में किसी की मजदूरी का नुकसान न हो। कोवारंटाईन की अवधि में मजदूरी का लागत सरकार वहन करे।

QUIEN SOSTIENE LA VIDA / *वो जो जीवन चलाते हैं, मैड्रिड, स्पेन*

हेनर डाइज विलहोज

स्टॉक एक्सचेंज खाली पड़े है, शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। आस–पड़ोस में एकजुटता के नेटवर्क बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही बजट–कटौतियों से जर्जर हो चुके सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को बचाने के लिए आवाजें उठ रही हैं। इस संघर्ष में सबसे आगे वो अनिश्चित श्रमिक हैं, जो खाद्य प्रावधान और सफाई जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनके कारण ही ख्सबका, जीवन चल रहा है।

2. स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक सुरक्षा को संगठित और सुचारू रूप से चलाया जाए। गरीबों में वितरण के लिए आपातकालीन अनाज स्टॉक को तुरंत जारी किया जाए।

3. सभी स्कूलों को बंद किया जाए।

4. अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों का तत्काल समाजीकरण हो ताकि संकट के समय वे लाभ की चिंता न करें। ये चिकित्सा केंद्र सरकार के स्वास्थ्य अभियान के नियंत्रण में होने चाहिए।

5. दवा कंपनियों का तुरंत राष्ट्रीयकरण किया जाए और उनके बीच तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित हो ताकि वैक्सीन और आसानी से परीक्षण करने वाले उपकरणों को निर्मित किया जाए। चिकित्सा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा को समाप्त किया जाए।

6. सभी लोगों का तत्काल परीक्षण किया जाए। इस महामारी से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के चिकित्साकर्मियों के लिए परीक्षणों और सहायता की तत्काल व्यवस्था की जाए।

7. संकट से निपटने के लिए आवश्यक सामग्रियों के उत्पादन की गति तुरंत बढ़ाई जाए (परीक्षण किट, मास्क, श्वासयंत्र)।

8. वैश्विक वित्तीय बाजारों को तत्काल बंद किया जाए।

9. सरकारों के दिवालियापन को रोकने के लिए वित्त की तत्काल व्यवस्था की जाए।

10. सभी गैर–कॉर्पोरेट ऋण को तत्काल रद्द किया जाए।

11. सभी किराए और गिरवी भुगतानों को तत्काल समाप्त किया जाए, साथ ही किसी को उनके घर से न निकाला जाए। बुनियादी मानवाधिकार के रूप में पर्याप्त आवास का तुरंत प्रावधान शामिल हो। राज्य द्वारा सभी नागरिकों को उचित आवास की गारंटी दी जाए।

12. राज्य द्वारा सभी उपयोगिता भुगतानों की वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए– पानी, बिजली और इंटरनेट मानवाधिकार के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाए। जहाँ ये सुविधाएँ सार्वभौमिक रूप से सुलभ नहीं हैं, हम उन्हें तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराने का आह्वान करते हैं।

13. क्यूबा, ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों पर प्रभाव डालने वाले एकतरफा, आपराधिक प्रतिबंधों और आर्थिक रुकावटों को तत्काल समाप्त किया जाए, जो आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति आयात करने में बाधक हैं।

14. स्वस्थ भोजन के उत्पादन को बढ़ाने और प्रत्यक्ष वितरण के लिए सरकार को आपूर्ति करने के लिए किसानों की तत्काल मदद दी जाए।

15. डॉलर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में निलंबित किया जाए। हम संयुक्त राष्ट्र से अनुरोध करते हैं कि तत्काल एक नया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए और समान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का प्रस्ताव करे।

16. प्रत्येक देश में एक सार्वभौमिक न्यूनतम आय (यूबीआई) सुनिश्चित किया जाए। इससे उन लाखों परिवारों को राज्य द्वारा सहायता की गारंटी मिल सकेगी जिनके पास कोई

काम नहीं है, जो बहुत दयनीय स्थिति में काम कर रहे हैं या जो अपना रोजगार करते हैं। वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था ने लाखों लोगों को औपचारिक नौकरियों से बाहर कर दिया है। राज्य को अपने लोगों के लिए रोजगार और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना चाहिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की लागत रक्षा बजट, विशेष रूप से हथियारों और गोला–बारूद के खर्च से निकाला जा सकता है।

ये सोलह बिंदु उत्तर–पूँजीवादी भविष्य के संघर्षों और नीतियों की ओर ध्यान देने तथा चर्चा और बहस के लिए एक घोषणापत्र है।

MADRES DE LA PLAZA, EL PUEBLO AÚN LAS ABRAZA | प्लाजा डे मेयो की माताओं, लोग तुम्हें अब भी अपने साथ रखते हैं

ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना

डेनिएला रूग्गेरी / ट्राईकॉन्टिनेंटल: सामाजिक शोध संस्थान

प्लाजा डे मेयो इस 24 मार्च को, 'सत्य और न्याय के स्मरण दिवस' के दिन खाली है। इस मार्च के इतिहास में पहली बार, हम 1976 में शुरू हुई तानाशाही के दौरान गायब कर दिए गए अपने साथियों के समर्थन में गलियों पर एकत्र नहीं हो सके। सोशल मीडिया पर और हमारी बालकनियों में, हमने अपनी प्लाजा डे मेयो की माताओं के लिए सफेद रुमाल लटकाए।

भाग 3. यूनिवर्सल बेसिक इनकम

पिछली आधी सदी के दौरान, यह स्पष्ट हो गया है कि रोजगार की पूरी व्यवस्था बिखर गई है। एक आधुनिक पूँजीवादी समाज में बेरोजगारी के कुछ प्रतिशत को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है (इसे 'बेरोजगारी की प्राकृतिक दर' के सिद्धांत रूप में निरूपित किया गया)। राज्य मजदूरी की कमी की भरपाई विभिन्न प्रकार की सामाजिक सहायता से करता रहा है। अब श्रम के वैश्वीकरण और उत्पादकता में प्रौद्योगिकी–प्रेरित वृद्धि के परिणामस्वरूप अरबों श्रमिक या तो बेरोजगार हैं, उनकी क्षमता के हिसाब से रोजगार नहीं हैं, या अत्यधिक अनिश्चितता की स्थिति में हैं (जैसे अल्पकालिक अनुबंध श्रमिक और दैनिक मजदूर)। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 25.8 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से कम–से–कम 15.7 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं जिन्हें अक्सर सामाजिक सुरक्षा उपायों से बाहर रखा जाता है। उनकी जोखिम भरी स्थिति की शायद ही कभी चर्चा होती है। सामाजिक असमानता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है और दुनिया की बहुसंख्यक आबादी के ऊपर गरीबी का संकट मंडरा रहा है।

पूँजीवाद के सबसे अधिक विस्तार वाले चरण में भी श्रमिकों के कुल आरक्षित बल का कुछ प्रतिशत अब भी बेरोजगार है। जब पूँजीवाद लाभप्रदता के दीर्घकालिक संकट का सामना कर रहा है, ऐसे में अधिकांश श्रमिक अत्यधिक अनिश्चितता का अनुभव कर रहे हैं। पूँजीवाद के तर्क के भीतर श्रमिकों का या तो अत्यधिक शोषण किया जा रहा है, या वे अधिशेष आबादी में तब्दील हो गए हैं। उनका जीवित रहना हताशा के स्तर तक पहुँच गया है।

पूँजीवाद के सामाजिक संबंधों के भीतर गरीबी और असमानता की इन समस्याओं से निपटने के लिए 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' का विचार सामने आया। यदि पूँजीपति अपने वित्तीय संसाधनों का उपयोग नौकरियों में निवेश करने के लिए नहीं करेंगे, तो इस अधिशेष आबादी को जिंदगी गुजारने के लिए कहीं और से कमाना होगा, चाहे वह पैसा सरकार ही को देना पड़े। यह राज्य–प्रायोजित भुगतान यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) के रूप में जाना जाता है। यह उपरोक्त घोषणापत्र के 16 वें बिंदु में है।

हमें यूबीआई की सीमाओं के बारे में साफ तौर पर पता होना चाहिए। यूबीआई विशाल अधिशेष आबादी को बेरोजगारी और अभाव से मुक्त करेगा, लेकिन यह लोगों को पूँजीवादी राज्य की शक्ति तथा धन–बल से मुक्ति नहीं देगा। नकद अदायगी का अर्थ है कि अभी भी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए नकदी की आवश्यक होगी, जो नकदी लेन–देन के बिना भी आवश्यकता के आधार पर प्रदान किया जा सकता है (उदाहरण के लिए, सार्वजनिक शिक्षा या सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली)। नवउदारवादी खेमे के लिए यूबीआई का आकर्षण इस बात में हैं कि वे अधिशेष आबादी के हाथों में नकदी देंगे, तब वे उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में भी सक्षम होंगे जिन्हें वे अभी खरीद नहीं पाते। पूँजीवाद के सामाजिक संबंधों को यूबीआई से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वह पूँजीवादी व्यवस्था के मानदंडों के भीतर महज एक सामाजिक कल्याण योजना है। व्यापक भूख और हताशा के इस माहौल में इस तरह की योजना का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, भले ही इसके प्रयोजन और किर्यान्वयन की सीमाएँ असीम हों।

पिछले कई दशकों में मार्क्सवादी नारीवादियों ने सामाजिक पुनरुत्पादन का शक्तिशाली सिद्धांत विकसित किया है, अर्थात् श्रम शक्ति का उत्पादन और उनका पुनरुत्पादन। सामाजिक पुनरुत्पादन या देखभाल का क्षेत्र जो मानव जीवन को पुनर्जीवन देता है, सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके बावजूद आय सहायता और मजदूरी के विषय में होने वाली चर्चा में इसे विशेष रूप से अनदेखा किया गया है।

सामाजिक पुनरुत्पादन का विश्लेषण करने के लिए पूँजीवाद के धन संचयन के चक्र तथा मानव श्रम शक्ति के नवीकरण और पुनरुत्पादन के पितृसत्तात्मक ढाँचे के आपसी संबंधों की व्याख्या करनी होगी। जो भी सामाजिक पुनरुत्पादन का काम करते हैं, खासकर महिलाएँ, शायद ही कभी उनके काम का मुआवजा मिलता है, जब तक उनके काम का व्यावसायीकरण न हो (जैसे कि नौकरानी सेवाओं, खाद्य उत्पादन और वितरण सेवाओं के माध्यम से)। श्रमिक वर्ग का पुनरुत्पादन पूँजीवादी उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, लेकिन श्रमिक वर्ग के पुनरुत्पादक स्वयं को व्यावसायिक रूप में (पैसे में) में मुआवजा नहीं दे पाते। यूबीआई के बारे में चल रही बहसों ने श्गृहकार्य के लिए मजदूरीश के बारे में और मजदूरी के विकल्प के रूप में यूबीआई की चर्चा को और तेज कर दिया है। यूबीआई या सामाजिक पुनरुत्पादन के काम के बराबर मुआवजा देने तथा विकलांग और अस्वस्थ लोगों की आजीविका की व्यवस्था करने के लिए किया जाने वाला तर्क मजबूत और शक्तिशाली है। हालाँकि एलेक्जेंड्रा कोल्लोनाई और एंजेला डेविस जैसे मार्क्सवादियों ने इस बात की ओर इशारा किया है कि देखभाल के काम का मुआवजा देने भर से इसकी भरपाई नहीं हो सकती क्योंकि ऐसे काम को हमेशा नीचा काम माना जाता रहा है, जिसकी जड़ें पितृसत्ता में धँसी हुई हैं। श्रम के लिंग आधारित विभाजन के विचार को तोड़ने के लिए पितृसत्ता के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करना होगा।

समाजवादियों से लेकर धुर–दक्षिणपंथियों तक यूबीआई का व्यापक रूप से समर्थन कर रहे हैं जो अभूतपूर्व है। सभी के पास इसके लिए एक अलग दृष्टि है और इस अंतर को सूचीबद्ध करना जरूरी है।

1. प्रतिस्थापन बनाम पूरक। यदि यह यूबीआई अन्य सभी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के बदले में होगा तो नवउदारवादी खेमा (और धुर–दक्षिणपंथी) इसे स्वीकार कर लेगा। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन और सार्वजनिक खाद्य वितरण जैसी नीतियों के एवज में यूबीआई को एक विकल्प के रूप में देखते हैं। सेवाओं के बजाये नकद देकर वे सामाजिक जीवन के इन अंगों को संशोधित करना चाहेंगे और फिर निश्चित रूप से उनका निजीकरण करेंगे। अधिशेष जनसंख्सया को वस्तु और सेवा बेचने के लिए पैसा उपलब्ध कराएँगे। यह सामाजिक सुरक्षा आवरण को खत्म करने और इसे निजीकरण करने की एक व्यवस्था भी है। समाजवादी तर्क यह है कि यूबीआई इन योजनाओं का विकल्प नहीं है, बल्कि उनका पूरक है। सार्वजनिक शिक्षा और सार्वजनिक भोजन वितरण जैसे सामाजिक मजदूरी को और बढ़ाया जाना चाहिए तथा व्यवस्थित करना चाहिए, यूबीआई की अलग से व्यवस्था की जाए जिसका इस्तेमाल बाकी जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

2. पात्रता–परीक्षण बनाम सार्वभौमिक अदायगी। नवउदारवादी खेमा यूबीआई को स्वीकार करता है, लेकिन फिर इस प्रस्ताव की मूल भावना को कमजोर कर देता है। वे इस बात को उठाते हैं कि यूबीआई को सार्वभौमिक नहीं होना चाहिए। वे कहते हैं कि हर किसी को न्यूनतम आय का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाये यह सुनिश्चित

करने के लिए पात्रता–परीक्षण होना चाहिए कि केवल जरूरतमंद को इस भुगतान का लाभ मिले। पात्रता–परीक्षण सार्वभौमिक आय के पूरे उद्देश्य को निष्फल कर देता है, जो पूरी जनसंख्या को एक बार फिर 'पात्र गरीब' और 'अपात्र गरीब' में बाँट देने के बजाये सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

सभी लोगों को आय सहायता प्रदान करने में कुछ असंगति भी है। बहुत अमीर लोगों को आय सहायता क्यों दी जाए? आय या वस्तुओं के सार्वभौमिक खर्च के लिए कई तर्क हैं:

i. कौन 'पात्र गरीब' या 'जरूरतमंद' है इसका निर्णय करने की नैतिक समस्या से बचने के लिए। इससे समाज में विभाजन पैदा होगा और लक्षित कल्याण भुगतान प्राप्त करने वालों को और अधिक कलंकित किया जाएगा।

ii- संस्थागत व्यवस्थाएँ जो हमेशा इन निर्णयों को लोकतांत्रिक तरीके से करने में सक्षम नहीं होती हैं और इन फंडों या सामानों के हस्तांतरण में हमेशा कुशल नहीं हीते हैं, चाहे वह 'आय' नकदी में हो या वस्तु में, व्यस्थाओं को ऐसे नैतिक निर्णयों से उत्पन्न कार्यान्वयन की भारी समस्याओं से बचाने के लिए।

iii- क्या अमीरों को नकद भुगतान धन के पुनर्वितरण के लक्ष्यों को कमजोर करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमीर ऐसी योजनाओं को चलाने के लिए वित्तीय मदद देते हैं, अपने धन का ऋण चुकाते हैं, जो ऋण उनको मिलने वाली आय सहाय ता से कहीं अधि ाक होगा।

यदि यूबीआई योजना सामाजिक मजदूरी के लिए एक विकल्प नहीं है परंतु इसके लिए एक पूरक है, और अगर यूबीआई योजना वास्तव में सार्वभौमिक है, तो पूँजीवादी व्यवस्था के उन्मूलन की दिशा में काम करते हुए वर्तमान पूँजावादी व्यवस्था में बहुत से लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए इसकी माँग करने में बहुस–सी संभावनाएँ छिपी हुई हैं। यदि यह सामाजिक मजदूरी का एक विकल्प है और यदि इसे कुछ लोगों को दिया जाता है, तो यह यूनिवर्सल बेसिक इनकम नहीं है, बल्कि सामाजिक लाभ को कम करने और निजीकरण करने तथा श्रमिक वर्ग के भीतर विभाजन बढ़ाने की खतरनाक व्यवस्था है।

यूबीआई के बारे में उठाए गए सवालों में से एक यह है कि राज्य इसके लिए भुगतान कैसे करेगा, और इसके आधार पर, काम करने योग्य प्रत्येक व्यक्ति को कितना वास्तविक आय भुगतान किया जाएगा। नवउदारवादी समाधान यह है कि अन्य सामाजिक कार्यक्रमों को बंद करके उस धन को एक कॉर्पस में शामिल कर दिया जाए और फिर वहाँ से नकद भुगतान हो। समाजवादी दृष्टिकोण से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे सामाजिक लाभ की योजनाओं का निजीकरण हो जाएगा, जिसे सार्वभौमिक मानवाधिकार माना जाना चाहिए। इसके बजाये समाजवादी व्यवस्था भुगतान के लिए कम–से–कम चार अलग–अलग स्रोतों पर निर्भर करेगा:

a- सम्पत्ति पर ऋण

b- कर क्षेत्राधिकार में वृद्धि और कर को पनाह देने तथा छिपाने वाले आश्रयों को समाप्त करना।

निष्कासन: कानून के समर्थन के साथ लोगों को उनकी संपत्ति से बलपूर्वक निकलना।

जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका

केट जोन्स वैन रेंसबर्ग / सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी

दक्षिण अफ्रीका के कोविद –19 राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान बेदखली पर रोक के बावजूद, सरकार ने निजी सुरक्षा बल, सेना और पुलिस की तैनाती कर लोगों को विस्थापित करना जारी रखा है। 1994 में रंगभेद की समाप्ति के बाद से, आवास के लिए लोगों के संघर्ष के प्रति सैन्यीकृत सरकार की प्रतिक्रिया ज्यों की त्यों बरकरार हैरू रंगभेद अब भी होता है।

c- सामाजिक रूप से अवांछनीय क्षेत्रों (उदाहरण के लिए आयुध) के करों में वृद्धि।

d- लाभ पर ऋण में वृद्धि।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य इस आय को एकत्र करने में सक्षम होगा, जो अन्यथा किसी ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ ऋण में छूट मिले, तो इसके लिए पूँजी पर नियंत्रण शुरू करने की आवश्यकता होगी। अगर यूबीआई योजना को आर्थिक संप्रभुता को विकसित करने के उपायों के एक हिस्से के रूप में लागू नहीं किया जाएगा, वह प्रभावी नहीं रह जाएग और फिर इसे विफलता के रूप में देखा जाएगा क्योंकि या तो ये पर्याप्त नहीं होगा (अगर पैसे नहीं मिले) या वर्तमान बजट पर बहुत अधिक भार पड़ जाएगा (यदि कोई नया कर नहीं लगाया जाता है)।1

कोरोना आपदा ने बेरोजगारी, अनिश्चितता और भूख की समस्याओं को बढ़ा दिया है। यूबीआई जिसे पूँजीवाद के तहत बेरोजगारी की पुनरावृत्ति के समाधान के रूप में माना जा रहा था अब COVID–19 रोग द्वारा उत्पन्न आपातकालीन संकट का एक उपाय बन गया है। एक बार फिर, नवउदारावदी तथा धुर–दक्षिणपंथी एक बार के नकद भुगतान से काफी खुश हैं क्योंकि एक ओर अनिश्चित रोजगार वाले तथा बेरोजगारों के गुस्से को कम किया जा सकता है तथा दूसरी ओर इसी पैसे से ठप पड़े व्यापार में फिर से माँग पैदा हो जाएगी। वास्तविक यूबीआई योजना के लिए बहुत कम रुचि है जो श्रमिक वर्ग को जीने का आधार दे सके।

निश्चित रूप से, बेरोजगारी का संकट दुनिया के कई हिस्सों में गंभीर खतरा है जो भूखमरी और अकाल के संकट के रूप में परिवर्तित हो रहा है। नकद हस्तांतरण तथा सार्वजनिक खाद्य वितरण जैसे तत्काल राहत कार्य समय की माँग है। आपातकाल के समय में, पीड़ा को दूर करने के लिए वे सभी उपाय जरूर करने चाहिए जो कर पाना संभव हो।

मजमून और मजदूर।

कुआलालंपुर, मलेशिया

इज़्रेना मारवान / मलेशिया डिजाइन आर्काइव

कोविद –19 महामारी में, मलेशिया की क्लैंग घाटी के एक निजी अस्पताल का दृश्य। एक निवारक उपाय के रूप में, मलेशिया में आवाजाही रोकने का ऑर्डर (MCO) जारी किया गया, जिसके तहत सब जगहें बंद और खाली हो गयीं। केवल स्वास्थ्य सेवा, चौकीदारी और फूड डिलीवरी के फ्रंटलाइन वर्करो को आनेजाने की अनुमति थी।

tricontinental

Instituto Tricontinental de Investigación Social es una institución promovida por los movimientos, dedicada a estimular el debate intelectual al servicio de las aspiraciones del pueblo.
www.eltricontinental.org

Instituto Tricontinental de Pesquisa Social é uma instituição internacional, organizado por movimentos, com foco em estimular o debate intelectual para o serviço das aspirações do povo.
www.otricontinental.org

Tricontinental: Institute for Social Research is an international, movement-driven institution focused on stimulating intellectual debate that serves people's aspirations.
www.thetricontinental.org